

[2012] 2 एस.सी.आर. 663

शोभन सिंह खनका

बनाम

झारखंड राज्य

आपराधिक अपील संख्या 592/2012

30 मार्च, 2012

**[न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम और न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर]**

*दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:*

धारा 438 - अग्रिम जमानत - राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों तथा परीक्षकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अंक में धांधली और छल संबंधी आपराधिक कार्यवाही - सतर्कता विभाग द्वारा जांच - प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज - अपीलकर्ता, एक विशेषज्ञ, को भी आरोपी के रूप में नामित किया गया - अपीलकर्ता की अग्रिम जमानत के लिए आवेदन विशेष न्यायाधीश और उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकृत - निर्णय: प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलकर्ता के खिलाफ सीमित आरोप और अन्य विवरणों को ध्यान में रखते हुए, उसकी शैक्षणिक योग्यताएँ, जिसमें यह तथ्य शामिल है कि वह राज्य का निवासी नहीं है और न ही उसके कोई रिश्तेदार हैं तथा वह झारखण्ड लोक सेवा आयोग का सदस्य नहीं है, केवल एक छोटे समय के लिए विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया है, अपीलकर्ता ने अग्रिम जमानत के लिए मामला प्रस्तुत किया है - यदि अभियोजन को कोई आशंका है, तो धारा 438 की उपधारा (2) संबंधित न्यायालय को ऐसे शर्त/निर्देश लागू करने की अनुमति देती है जो वह उचित समझे - अपीलकर्ता को गिरफ्तारी की स्थिति में जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया, निर्णय में निर्धारित शर्तों के अधीन।

धारा 438 - अग्रिम जमानत - विचार करने वाले कारक - स्पष्ट किया गया।

एक जांच के दौरान जो सतर्कता विभाग द्वारा की गई थी, यह खुलासा हुआ कि झारखंड लोक सेवा आयोग की दूसरी सिविल सेवाओं की परीक्षा - 2005 में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, धांधली, अंक छेड़छाड़, परीक्षकों की नियुक्ति में अनियमितता और साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों तथा अध्यक्ष ने सफल उम्मीदवारों के साथ साजिश करके अधिकारियों को आर्थिक लाभ पहुँचाने के लिए भ्रष्ट तरीकों का सहारा लिया। उन्होंने विभिन्न व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए सरकार को सिफारिशें की। यह भी आरोप लगाया गया कि सदस्यों ने परीक्षा में उपस्थित अपने रिश्तेदारों के बारे में घोषणा नहीं की या आवश्यक विवरण प्रदान

नहीं किए। कई व्यक्तियों के खिलाफ, जिसमें अध्यक्ष और झारखण्ड लोक सेवा आयोग के सदस्य शामिल थे, एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इससे भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत विशेष मामला संख्या 23/2010 का जन्म हुआ।

आवेदक ने अग्रिम जमानत के लिए आपराधिक दंड संहिता की धारा 438 के तहत आवेदन किया जिसे विशेष न्यायाधीश और उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।

अपील को स्वीकार करते हुए, अदालत ने कहा:

1.1. यह स्थापित कानून है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक मूल्यवान मौलिक अधिकार है। गिरफ्तारी से पहले जमानत के दावे पर विचार करते समय निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाना चाहिए: (i) आरोप की प्रकृति और गंभीरता; (ii) आवेदक का पूर्व इतिहास; (iii) न्याय से भागने की संभावना; और (iv) क्या आरोप आवेदक को चोट पहुँचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं।

1.2. यह विवादित नहीं है कि आवेदक झारखण्ड लोक सेवा आयोग का नियमित सदस्य नहीं है और न ही वह झारखंड राज्य से संबंधित है। वह केंद्रीय सरकार की सेवा में है और उसे बोर्ड द्वारा विशेषज्ञ नंबर 1 के रूप में नामित किया गया था। आवेदक का शैक्षणिक करियर उत्कृष्ट है।

1.3. प्राथमिकी का अध्ययन करने पर यह भी दिखाता है कि आवेदक उन उम्मीदवारों से परिचित नहीं था या उनके साथ कोई संबंध नहीं था जिनका साक्षात्कार उस पैनल द्वारा लिया गया था जिसमें वह सदस्य था।

1.4. विशेष न्यायाधीश और उच्च न्यायालय द्वारा आवेदक की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने का आदेश रद्द कर दिया गया है। यदि गिरफ्तारी होती है, तो आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाएगा, जो निर्णय में निर्धारित शर्तों के अधीन होगा।

अपराध अपीली अधिकारिता: आपराधिक अपील संख्या 592/2012

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के निर्णय एवं आदेश दिनांक 21.09.2011 से एबीए संख्या 3230/2011

उदय यू. लालित, नितिन संगरा, सत्यजीत साहा, वी.डी. खन्ना आवेदक के लिए।

सुनील कुमार, छाया कुमारी, अनिल के. झा प्रतिवादी के लिए।

अदालत का निर्णय न्यायमूर्ति पी. सत्यसिवम, द्वारा दिया गया। 1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा 21.09.2011 को पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ है जिसमें आवेदक द्वारा दायर अग्रिम जमानत के आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

3. संक्षिप्त तथ्य:

(क) आवेदक, जो झारखंड लोक सेवा आयोग (संक्षेप में "झारखण्ड लोक सेवा आयोग") के साक्षात्कार बोर्ड में एक विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत था, ने विशेष न्यायाधीश (सतर्कता) के समक्ष धारा 438 आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में "संहिता") के तहत अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की, जो विशेष मामला संख्या 23/2010 से संबंधित है, जो सतर्कता थाना संख्या 23/2010 के अंतर्गत धारा 420, 423, 424, 467, 468, 469, 471, 477ए, 120-B, 109 और 201 भारतीय दंड संहिता, 1908 (संक्षेप में "भारतीय दंड संहिता") और धारा 13(2) पढ़ने के साथ धारा 13(1)(सी)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत उत्पन्न हुआ।

(ख) आवेदक के अनुसार, उसे सूचित किया गया था कि उसे साक्षात्कार बोर्ड में विशेषज्ञ नंबर 1 के रूप में नामित किया गया था ताकि साक्षात्कार लिया जा सके जो 28.01.2008 से 01.02.2008 तक आयोजित किया गया। उसे झारखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित विशेषज्ञ समिति के सदस्यों द्वारा चयनित किया गया था।

(ग) आवेदक, अध्यक्ष और झारखण्ड लोक सेवा आयोग के अन्य सदस्यों के खिलाफ आरोप हैं कि उन्होंने उन उम्मीदवारों को उच्चतम अंक प्रदान किए जिन्हें वे चयनित या नियुक्त करना चाहते थे। आवेदक भी अध्यक्ष, झारखण्ड लोक सेवा आयोग के सदस्यों और उन उम्मीदवारों के साथ साजिश का जिम्मेदार है जिन्हें साक्षात्कार बोर्ड द्वारा उच्चतम अंक दिए गए थे। यह भी आरोप लगाया गया है कि आवेदक ने चयन और नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को लाभ पहुँचाने हेतु साक्षात्कार बोर्ड की अंक तालिका में कटौती, छेड़छाड़ और हस्तक्षेप किया।

(घ) अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि सतर्कता विभाग द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और अधिकारियों द्वारा दूसरी झारखण्ड लोक सेवा आयोग सिविल सेवाओं की परीक्षा आयोजित करने में की गई अनियमितताओं के संबंध में जांच की गई थी। अभियोजन का आरोप है कि परीक्षा दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं आयोजित की गई थी। सदस्यों ने या तो परीक्षा में उपस्थित अपने रिश्तेदारों के बारे में घोषणा नहीं की या जिन्होंने घोषणा की है उन्होंने आवश्यक विवरण प्रदान नहीं किए। अभियोजन का आगे का आरोप है कि छात्रों को दिए गए अंकों में छेड़छाड़ हुई है। अभियोजन ने 22 प्रतियां जांची हैं और आरोप लगाया गया है कि उन्हें उत्तर पुस्तिकाओं में छेड़छाड़ मिली है। अभियोजन का आगे का मामला यह है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, छेड़छाड़, अंक छेड़छाड़, परीक्षकों की

नियुक्ति में अनियमितता और अध्यक्ष ने सदस्यों के साथ मिलकर और सफल उम्मीदवारों के साथ साजिश करके झारखण्ड लोक सेवा आयोग अधिकारियों को आर्थिक लाभ पहुँचाने के लिए भ्रष्ट तरीकों का सहारा लिया। इसके लिए विभिन्न व्यक्तियों की नियुक्ति हेतु सरकार को सिफारिशें की गईं। इस प्रकार कई व्यक्तियों के खिलाफ एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में "प्राथमिकी") दर्ज की गई जिसमें आवेदक भी शामिल था।

(e) दिनांक 01.08.2011 को विशेष न्यायाधीश (सतर्कता) रांची ने सामग्री पर विचार करते हुए आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया और उसकी याचिका खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ, आवेदक ने झारखंड उच्च न्यायालय में एबीए संख्या 3230/2011 दायर की। अपीलित आदेश दिनांक 21.09.2011 को उच्च न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश का आदेश पुष्टि करते हुए उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

4. हमने आवेदक के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उदय यू. लालित और झारखंड राज्य के प्रतिवादी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुनील कुमार की सुनवाई की।

5. सभी सामग्रियों, जिसमें प्राथमिकी और वर्तमान आवेदक से संबंधित आरोप शामिल हैं, को देखने के बाद, श्री लालित, वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्राथमिकी में यह उल्लेख करने के अलावा कि आवेदक एक विशेषज्ञ था, ऐसा कुछ नहीं है जो आवेदक को किसी अपराध से, विशेष रूप से वहां लगाए गए आरोपों से जोड़ सके। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदक जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का निवासी है और वर्तमान में हरियाणा के फरीदाबाद में तैनात है, झारखंड राज्य में कोई रिश्तेदार, मित्र या संबंधी नहीं है और इसलिए किसी को भी लाभ पहुँचाने या किसी साजिश का हिस्सा बनने का उसका कोई कारण या उद्देश्य नहीं था। उन्होंने आगे बताया कि आवेदक की भूमिका एक विशेषज्ञ सदस्य के रूप में केवल प्रत्येक उम्मीदवार को अलग-अलग शीट पर अंक देना था और इसके अलावा उनका कोई कार्य नहीं था। उन्होंने यह भी बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा अपीलित आदेश में आवेदक को अन्य आरोपियों के समान स्थिति में रखने की टिप्पणी तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि आवेदक को झारखंड राज्य के अन्य विशेषज्ञों के मामले में नहीं रखा जा सकता है जो उन उम्मीदवारों से संबंधित या परिचित हैं और इसलिए उनके पास अपराध करने का कोई कारण या उद्देश्य नहीं था। दूसरी ओर, राज्य के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपराध की गंभीरता और इस तथ्य को देखते हुए कि आवेदक का प्रारंभिक चयन विशेषज्ञ के रूप में स्वयं नियमों के खिलाफ है और चयन पैनल में शामिल सभी व्यक्तियों द्वारा कई छेड़छाड़ की गई हैं, यह एक ऐसा मामला नहीं है जिसमें अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए।

6.हमने प्रासंगिक सामग्रियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और प्रतिकूल तर्कों पर विचार किया है।

7.चूंकि हम अग्रिम जमानत देने की पात्रता या अन्यथा के बारे में चिंतित हैं, इसलिए सभी तथ्यात्मक विवरणों में जाने की आवश्यकता नहीं है और इस पर एक निष्कर्ष पर पहुँचने की आवश्यकता नहीं है जो मामले की अंतिम सुनवाई को प्रभावित करेगा। हमने पहले ही प्राथमिकी में लगाए गए अपराधों का उल्लेख किया है। यह स्थापित कानून है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक मूल्यवान मौलिक अधिकार है। इस पृष्ठभूमि में, हमें देखना होगा कि क्या अग्रिम जमानत देने का मामला बनाया गया है।

8.यह विवादित नहीं है कि वह झारखण्ड लोक सेवा आयोग का नियमित सदस्य नहीं है। वह केंद्रीय सरकार की सेवा में है और उसे बोर्ड द्वारा विशेषज्ञ नंबर 1 के रूप में नामित किया गया था। हालांकि यह बताया गया है कि उसकी नामांकन स्वयं गलत है, यह इस समय एक प्रासंगिक मुद्दा नहीं है। श्री लालित, आवेदक के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता ने उसकी उच्च शैक्षणिक योग्यताओं का उल्लेख किया। ये सभी विवरण अनुबंध-पी 1 में उपलब्ध हैं जो दिखाते हैं कि आवेदक के पास एमकॉम. (स्वर्णपदक प्राप्त) की योग्यताएँ हैं और उसके पास 5 पीएच.डी. हैं। वह केंद्रीय सरकार के राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर और फेलो प्रोग्राम और प्रबंधन में समन्वयक हैं और उन्हें 21.10.1994 से प्रोफेसर के रूप में 16 वर्षों का अनुभव है। उनके पास व्यवसाय प्रशासन विभाग के प्रमुख के रूप में 13 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव और प्रबंधन अध्ययन स्कूल में डीन के रूप में 13 वर्षों का अनुभव है। आवेदक मानव संसाधन प्रबंधन, संगठनात्मक व्यवहार और उद्यमिता विकास में विशेषज्ञता रखता है और इसके अलावा, उनके पास अन्य विदेशी देशों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अंतरराष्ट्रीय अनुभव भी है। यह भी बताया गया कि आवेदक यूजीसी, एआईसीटीआई, आईसीएसएसआर और अन्य विश्वविद्यालयों की चयन समितियों में नियमित विशेषज्ञ रहा है। उनके खाते में कई शोध/संदर्भ पुस्तकें और पाठ्यपुस्तकों की लेखनता भी है। हाल ही में 26.05.2011 को उन्हें अरुणाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल द्वारा "शिक्षा रत्न पुरस्कार" से सम्मानित किया गया। यह भी हमारे ध्यान में लाया गया कि जुलाई 2011 में भारत के माननीय राष्ट्रपति ने आवेदक की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उन्हें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमर कांतक, मध्य प्रदेश में सहायक/संबद्ध प्रोफेसरों की भर्ती के लिए अपना नामांकित व्यक्ति बनाया। उपरोक्त विवरण दर्शाते हैं कि आवेदक का शैक्षणिक करियर उत्कृष्ट है।

9.प्राथमिकी में आवेदक को आरोपी संख्या 7 के रूप में नामित किया गया है। हालांकि यह बताया गया कि आवेदक ने उन उम्मीदवारों को उच्चतम अंक दिए जिन्होंने साक्षात्कार बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा केवल 10 अंक प्राप्त किए थे, यह विवादित नहीं है कि वह झारखण्ड लोक सेवा आयोग बोर्ड का सदस्य नहीं है न ही झारखंड राज्य से संबंधित है। जैसा कि पहले कहा गया था, उन्हें केवल एक छोटे समय के

लिए विशेषीकृत सदस्य के रूप में चयनित किया गया था। श्री लालित ने हमें चार्ट दिखाया जिसमें विशेषज्ञों द्वारा दिए गए अंकों को दर्शाया गया है जिसमें वर्तमान आवेदक - विशेषज्ञ नंबर 1, विशेषज्ञ नंबर 2 और अध्यक्ष शांति देवी शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि अध्यक्ष ने प्रत्येक उम्मीदवार को उसके प्रदर्शन की परवाह किए बिना 10 अंक दिए हैं। हम यहां यह मूल्यांकन करने या निष्कर्ष देने के लिए नहीं हैं कि आवेदक (विशेषज्ञ नंबर 1) द्वारा दिए गए अंक अत्यधिक या असंगत हैं। इन सभी बातों का विश्लेषण केवल सबूतों द्वारा सुनवाई के समय किया जाना चाहिए।

10. हालांकि उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि समानता के आधार पर और इसी प्रकार की स्थिति में अन्य सह-आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया गया, हम इस पर विचार करते हैं कि चूंकि बोर्ड के सभी अन्य सदस्य, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल हैं, झारखंड से संबंधित हैं और उनके कुछ रिश्तेदार चयन में शामिल हुए थे, और यह देखते हुए कि वर्तमान आवेदक का झारखण्ड लोक सेवा आयोग से कोई संबंध नहीं है और वह उत्तराखंड राज्य से है, यह अवलोकन/निष्कर्ष स्वीकार्य नहीं है।

11. प्राथमिकी का अध्ययन करने पर यह भी स्पष्ट होता है कि आवेदक उन उम्मीदवारों से परिचित नहीं था या उनके रिश्तेदार नहीं थे जिनका साक्षात्कार उस पैनल द्वारा लिया गया था जिसमें वह सदस्य था। यह देखते हुए कि आवेदक झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है और झारखंड राज्य में कोई रिश्तेदार, मित्र या संबंधी नहीं है, उसके खिलाफ आरोपित साजिश में उसे शामिल करने का कोई प्राइम फेशी मामला नहीं है। उसकी शैक्षणिक योग्यताओं और अनुभव को देखते हुए और यह ध्यान में रखते हुए कि उसका शैक्षणिक करियर बेजोड़ है और यह तथ्य कि उसे झारखंड राज्य में कोई रुचि नहीं है, हम मानते हैं कि आवेदक ने धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए एक मामला बनाया है।

12. गिरफ्तारी से पहले जमानत के दावे पर विचार करते समय निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाना चाहिए:

(i) आरोप की प्रकृति और गंभीरता;

(ii) आवेदक का पूर्व इतिहास, जिसमें यह तथ्य शामिल है कि क्या वह किसी संज्ञानीय अपराध के संबंध में अदालत द्वारा सजा काट चुका है;

(iii) न्याय से भागने की संभावना; और

(iv) जब आरोप ऐसा किया गया हो कि आवेदक को गिरफ्तार करके उसे चोट पहुँचाने या अपमानित करने का उद्देश्य हो।

प्राथमिकी में सीमित आरोप और अन्य विवरणों को देखते हुए, उसकी शैक्षणिक योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि वह झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है, उसके पास कोई रिश्तेदार नहीं है और वह झारखण्ड लोक सेवा आयोग का सदस्य नहीं है, केवल एक छोटे समय के लिए विशेषज्ञ नंबर 1 के रूप में कार्य किया है, आवेदक ने अग्रिम जमानत के लिए एक मामला बनाया है। यदि अभियोजन को कोई आशंका है, तो धारा 438 की उपधारा (2) संबंधित अदालत को ऐसी शर्तों/निर्देश लगाने की अनुमति देती है जो वह उचित समझे।

13. इन परिस्थितियों में, विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश और उच्च न्यायालय द्वारा उसकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने वाले आदेश को रद्द किया जाता है। तदनुसार, हम निर्देश देते हैं कि यदि गिरफ्तारी होती है, तो आवेदक को थाना मामला संख्या 23/2010 के संबंध में विशेष मामला संख्या 23/2010, सतर्कता थाना, रांची, झारखंड में निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएगा:

(i) आवेदक आवश्यकतानुसार पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेगा;

(ii) आवेदक सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट करने से रोकने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा;

(iii) आवेदक विशेष अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

14. यह स्पष्ट किया जाता है कि हमारे द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष केवल अग्रिम जमानत के आवेदन के निपटान तक सीमित है और विशेष न्यायाधीश आरोपों का निर्णय अंतिम सुनवाई में कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, बिना यहाँ किए गए किसी भी अवलोकन/निष्कर्ष से प्रभावित हुए।

15. उपरोक्त शर्तों पर अपील स्वीकार की जाती है।

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है।